बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग हम लोगों की पुरानी : अशोक चौधरी

अशोका एक्सप्रेस

SMA - Ashoka Express Publication

Member : CNSI, Delhi निर्वाण प्राप्त गीता भारती राष्ट्रीय हिन्दी साप्ताहिक

Website :-www.ashokaexpress.com YouTube ashokaexpress

E-mail :-ashoka.express@live.com ashokaexpress

संपादक :- विजय कुमार भारती
प्रबंधक :- सज्जन सिंह

● वर्ष: 27 ● अंक : 24 ● नई दिल्ली ● 01 से 08 जुलाई 2024 ● पृष्ठ : 8 ● मूल्य : 2 रूपये

अभी तक नहीं उठा टर्मिनल-1 का मलबा, हादसे के बाद आज भी 35 फ्लाइट्स रद्द

नई दिल्ली। दिल्ली एयरपोर्ट पर हादसे के बाद टर्मिनल-1 पर हवाई यातायात सामान्य नहीं हो पाया है। फ्लाइट्स अभी भी टर्मिनल-2 और 3 से ऑपरेट हो रही हैं। इन टर्मिनल पर भीड़ पहले से होने के चलते उड़ानों में देरी हो रही है। साथ ही कई उड़ानों को रद्द किया गया है। बता दें कि हादसे के बाद से टर्मिनल-1 की सभी उड़ानें टर्मिनल-2 और 3 से आ और जा रही हैं। टर्मिनल-1 से इंडिगो और स्पाइसजेट एयरलाइंस की घरेलू उड़ानें ऑपरेट होती हैं। जानकारी के अनुसार, अभी तक करीब 35 उड़ानें रद्द होने की जानकारी मिल रही है। उड़ानों में लेटलतीफी की बात हो तो आधे से आठ घंटे तक का विलंब देखा जा रहा है। विलंबित उड़ानों में आधा घंटा का विलंब सामान्य है। टर्मिनल-1 अभी भी बंद पड़ा है। यहां से मलबे को नहीं हटाया गया है।

हमें जेल से निकले केवल 2 दिन हुए, अभी से ही विपक्ष के लोगों में खलबली मची, हूल दिवस पर बोले हेमंत सोरेन

रांची। हेमंत सोरेन ने हूल दिवस के अवसर पर साहिबगंज जिले के भोगनाडीह में जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विगत 5 महीने के बाद जेल से छूटने के बाद मेरा यह पहला घर से बाहर निकलना है जहां आज मैं हूल दिवस पर पहुंचा हूं और यह संयोग है यह हूल दिवस तो हम सदियों से मना रहे हैं, लेकिन आज यह मेरे लिए हमारे झारखंड वासियों के लिए आदिवासी-मूल वासियों के लिए एक प्रेरणा दिवस है। हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी हमको जेल से निकले केवल 2 दिन हुए है। अभी से ही विपक्ष के लोगों में खलबली मच गई है। उन्होंने कहा कि अब देश के बड़े-बड़े नेता मेरे आगे-पीछे घूमने लगे हैं कि किस तरीके से मुझे फंसाया जाए। मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जाए और मुझे जेल में डाला जाए। हेमंत सोरेन ने कहा कि हमने संकल्प लिया है कि इन सामंती सोच मनुवादी विचारधारा वाले लोगों की जड़ राय और देश से कबाड़ देंगे। अलग-अलग झूठे मुद्दों को लेकर महागठबंधन के नेताओं को फंसाया गया। इन लोगों ने किसी को नहीं छोड़ा चाहे वह राहुल गांधी हो, केजरीवाल हो या फिर हेमंत सोरेन हो। मनगढ़ंत कहानी, फर्जी केस पर जिसका कोई साक्ष्य नहीं उसमें फंसाकर जेल में भेजा। हेमंत सोरेन ने कहा कि इनको पता नहीं की झारखंड एक ऐसा धरती है जो पूरा खून से सना हुआ। यह शहीदों की धरती है इधर सिद्धू-कान्हू है तो उधर भगवान बिरसा मुंडा हैं, चंद भैरव है इधर नीलांबर-पीतांबर है। हमको ये क्या डराएंगे। उन्होंने कहा कि आज महंगाई आसमान छू रहा है। जब हम सरकार बनाए थे तो खनिज से 1 करोड़ 36,000 लाख का बकाया केंद्र सरकार के पास था जब हमने उसे मांगना शुरू किया तो हम जेल में डाल दिया। हमें भी लगा कि यह हमारा हक मांगने का परिणाम है।

झारखंड में जमींदोज हुआ निर्माणाधीन पुल, भारी बारिश के कारण हुआ हादसा

गिरिडीह । बिहार के बाद अब झारखंड में एक निर्माणाधीन पुल गिर गया है। यह पुल गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड में अरगा नदी पर बना रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक, शनिवार देर रात को हुई बारिश के बाद पुल का पिलर धंस गया था, जिसकी वजह से गर्डर टूटा और पुल जमींदोज हो गया। जानकारी के लिए बता दें कि इस पुल का निर्माण पथ निर्माण विभाग द्वारा साढ़े पांच करोड़ की लागत से करवाया जा रहा था। गिरिडीह से सड़क निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता विनय कुमार ने पीटीआई-भाषा को बताया, पुल का निर्माण कार्य किया जा रहा है। शनिवार रात भारी बारिश के कारण पुल का सिंगल-स्पैन गर्डर गिर गया और एक पिलर झुक गया। ठेकेदार को उस हिस्से को दोबारा बनाने के लिए कहा गया है।

कांग्रेस बोली- 50 फीसदी से अधिक हो आरक्षण की सीमा, संसद को पारित करना चाहिए कानून

नई दिल्ली। कांग्रेस ने रविवार को कहा कि संसद को एक कानून पारित करना चाहिए, ताकि आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से अधिक हो सके। विपक्षी पार्टी की ओर से यह बयान तब सामने आया है, जब एक दिन पहले जद (यू) ने बिहार में आरक्षण की सीमा को नौवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की। जनता दल (यूनाइटेड) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की शनिवार को बैठक हुई। जिसमें पार्टी ने उच न्यायालय के हालिया उस फैसले पर चिंता जताई। जिसमें बिहार सरकार के अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी कर दी गई। बैठक में एक राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किया

गया। जिसमें जदयू ने भाजपा के नेतृतत्व वाली केंद्र सरकार से राय के कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची में डालने का अनुरोध किया, ताकि उसकी न्यायिक समीक्षा की संभावना खारिज की जा सके। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान विपक्षी पार्टी कहती रही है कि एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण से जुड़े राय के सभी कानूनों को नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, यह अछी बात है कि जद (यू) ने कल पटना में यही मांग उठाई है। लेकिन उसकी सहयोगी भाजपा राय और केंद्र दोनों जगह इस मामले पर पूरी तरह चुप है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, आरक्षण कानूनों को 50 फीसदी की सीमा से परे नौवीं अनुसूची में लाना भी कोई समाधान नहीं है, क्योंकि 2007 के सर्वोच न्यायालय के फैसले के अनुसार ऐसे कानून न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए संविधान संशोधन कानून की जरूरत है। उन्होंने कहा, ऐसी स्थिति में संसद के पास एकमात्र रास्ता यह है कि वह संविधान संशोधन विधेयक पारित करे, जिससे एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण 50 फीसदी से यादा हो सके।

मनोज कुमार सिंह बने प्रदेश के नए मुख्य सचिव, संभाला कार्यभार, डीएस मिश्रा को नहीं मिला चौथा सेवा विस्तार

लखनऊ । 1988 बैच के आईएएस अफसर मनोज कुमार सिंह यूपी के मुख्य सचिव बनाए गए हैं। उन्होंने शाम करीब चार बजे अपने कार्यालय में पद भार संभाल लिया है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि दुर्गा शंकर मिश्रा को एक बार और सेवा विस्तार मिल सकता है। कयास के उलट मनोज कुमार सिंह प्रदेश के मुख्य सचिव बनाए गए। रविवार दोपहर वह अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। मनोज कुमार सिंह मुख्य सचिव और IIDC दोनों होंगे। मनोज कुमार सिंह 1987 बैच के अरुण सिंघल, इसी बैच की लीना नंदन और 1988 बैच के रजनीश दुबे को सुपरसीड करके मुख्य सचिव बनाए गए हैं। अरुण सिंघल और लीना नंदन केंद्रीय नियुक्ति पर हैं, जबकि रजनीश दुबे राजस्व परिषद के अध्यक्ष हैं। मनोज कुमार सिंह 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वे

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफी भरोसेमंद माने जाते हैं। यही वजह है कि पिछले काफी समय से कृषि उत्पादन आयुक्त और अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रहे थे। इससे पहले मनोज कुमार सिंह ललितपुर, गौतम बुद्ध नगर, पीलीभीत और मुरादाबाद के जिलाधिकारी रह चुके हैं। ग्राम विकास आयुक्त की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी उन्होंने निभाई। मुरादाबाद के मंडल आयुक्त भी रहे हैं। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, ग्राम्य विकास, पंचायती राज जैसे महत्वपूर्ण विभागों के अपर मुख्य सचिव की जिम्मेदारी भी उन्होंने बखूबी निभाई। वह भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में संयुक्त सचिव भी रहे हैं।

आज संसद में जोरदार हंगामे के आसार

नयी दिल्ली। संसद की कार्यवाही के सोमवार को पुन आरंभ होने पर, राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) प्रश्नपत्र लीक, अग्निपथ योजना और महंगाई जैसे मुद्दों पर जोरदार बहस होने की संभावना है। विपक्ष प्रश्नपत्र लीक मामले के अलावा बेरोजगारी का मुद्दा भी उठा सकता है। लोकसभा में, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। भाजपा की दिवंगत नेता सुषमा स्वराज की बेटी एवं पहली बार की लोकसभा सदस्य बांसुरी स्वराज इस प्रस्ताव का अनुमोदन करेंगी। लोकसभा ने धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 16 घंटे का समय निर्धारित किया है, जिसका समापन मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जवाब के साथ होगा। रायसभा में चर्चा के लिए 21 घंटे का समय निर्धारित किया गया है और प्रधानमंत्री के बुधवार को (चर्चा पर) जवाब देने की संभावना है। नीट मुद्दे पर संसद में इस सप्ताह काफी हंगामा हुआ। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने पांच मई को नीट-यूजी का आयोजन किया था, जिसमें करीब 24 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे। नतीजे चार जून को घोषित किए गए, लेकिन इसके बाद बिहार जैसे रायों में प्रश्नपत्र लीक होने के अलावा परीक्षा से जुड़ी अन्य अनियमितताओं के आरोप लगे। रायसभा में चर्चा की शुरुआत करते हुए भाजपा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी ने मोदी को ''अतुलनीय'' बताया था और कहा था कि देश के सामने आने वाले मुद्दों से निपटने के उनके दृष्टिकोण और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण में बहुत अंतर है। भाजपा सदस्य कविता पाटीदार ने प्रस्ताव का समर्थन किया था और चर्चा में अब तक नौ अन्य सदस्य भाग ले चुके हैं। लोकसभा में शुक्रवार को विपक्षी सदस्यों ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा 'नीट-यूजी' में कथित अनियमितता पर चर्चा कराने की मांग को लेकर हंगामा किया, जिस कारण सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। नीट विवाद पर चर्चा कराने की मांग को लेकर विपक्ष ने रायसभा में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया तथा विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे भी अपने साथी सदस्यों के साथ आसन के करीब आ गए। नीट मुद्दे पर हंगामे के बीच छत्तीसगढ़ से कांग्रेस सांसद फूलो देवी नेताम उच रक्तचाप के कारण अचानक बेहोश हो गईं, जिसके बाद उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। विपक्षी दलों के सदस्यों ने सदन की कार्यवाही स्थगित न करने तथा रायसभा सदस्य के स्वास्थ्य की चिंता न करने के लिए सरकार की आलोचना की।

सम्पादकीय

वर्तमान संघर्षों में पुरानी अवधारणाओं को लागू करना

इतिहास हमें बताता है कि भू-रणनीतिक परिवर्तन कभी भी आसान नहीं होते। वे जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हमेशा अनिश्चितता, भय, असुरक्षा और रक्तपात के साथ होते हैं। हालांकि हर परिवर्तन अपने साथ कुछ वैचारिक निर्माण लाता है जो अगले दशक या सदियों तक रणनीतिक परिदृश्य को रेखांकित करता है। यह स्थायी शांति के युग की शुरूआत करता है जो आमतौर पर समृद्धि, मानव जाति की आगे की यात्रा और सबसे बढ़कर स्थिरता और थोड़ी-सी खुशी के साथ होता है। अगर कोई इतिहास में गहराई से जाए तो 1618 में रोमन कैथोलिक और प्रोटैस्टैंट के बीच शुरू हुए 30 साल के युद्ध ने मध्य यूरोप के अधिकांश हिस्से को तबाह कर दिया था। 1648 में वेस्टफेलिया की शांति के साथ शांत हुए उस विनाश की राख से एक नया सिद्धांत उभरा जिसने एक सदी या उससे अधिक समय तक यूरोपीय राज्य शिल्प को आधार बनाया। इसे रायसन डी'एटैट कहा जाता है। इसे चर्च के एक राजकुमार आर्मंड जीन डु प्लेसिस, कार्डिनल डी रिचेल्यू द्वारा गढ़ा गया, जो 1624-1642 तक फ्रांस के प्रथम मंत्री थे, और उसके बाद से अधिकांश यूरोपीय शक्तियों द्वारा इसका अनुसरण किया गया। रायसन डी'एटैट इस तथ्य पर आधारित था कि किसी राष्ट्र की सुरक्षा और प्रधानता के लिए उसे संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए आवश्यक सभी साधनों की तैनाती की आवश्यकता होती है। इसने परिकल्पना की कि सर्वोच्च राष्ट्रीय हित को सार्वभौमिक नैतिकता की सभी पुरातन धारणाओं से दूर रहना चाहिए। इसलिए रायसन डी'एटैट एक जटिल परिकल्पना पर आधारित था कि प्रत्येक राष्ट्र अपने स्वार्थी और संकीर्ण हितों का पीछा करते हुए किसी न किसी तरह से सभी अन्य लोगों की सामूहिक सुरक्षा और प्रगति को सुनिश्चित करेगा। हालांकि 18वीं शताब्दी तक ग्रेट ब्रिटेन ने शक्ति संतुलन की अवधारणा को स्पष्ट कर दिया था, जो अगले 200 वर्षों तक यूरोपीय कूटनीति पर हावी रहा। इसकी उत्पत्ति ब्रिटिशों की इच्छा में हुई थी कि वे किसी भी एक यूरोपीय शक्ति को यूरोपीय महाद्वीप पर हावी होने से रोकें। संतुलन बनाए रखने के लिए ग्रेट ब्रिटेन को किसी भी संघर्ष में कमजोर या कमजोर पक्ष के पीछे अपना वजन डालना पड़ता था। शक्ति संतुलन की अवधारणा का उपयोग ऑस्ट्रिया के राजकुमार वॉन मेटरनिख और अन्य यूरोपीय राजनेताओं ने सितंबर 1814 में वियना की कांग्रेस में यूरोप में सामंजस्य स्थापित करने के लिए किया था। इसने सुनिश्चित किया कि 40 वर्षों तक महाशक्तियों के बीच कोई युद्ध न हो और 1854 के क्रीमियन युद्ध के बाद अगले 60 वर्षों तक कोई सामान्य युद्ध न हो, जिससे एक सदी तक सापेक्ष शांति सुनिश्चित हुई जिसने यूरोप को भौतिक, सांस्कृतिक और साम्राज्यवादी रूप से फलने-फूलने में मदद की। मैंने इन 3 सिद्धांतों अर्थात् रीजन डी'एटैट , शक्ति संतुलन और वास्तविक राजनीति को प्रतिपादित करने का कारण इसलिए चुना है क्योंकि उस युग के राजनेताओं द्वारा अवधारणा को लागू किए जाने के कई शताब्दियों बाद भी वे अलग-अलग नामों के तहत काम करना जारी रखते हैं क्योंकि दुनिया 3 महाद्वीपों में सक्रिय संघर्षों के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सामूहिक शांति के लिए शायद सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रही है।

पेपर लीक पर जीएसटी की ज़रूरत

चुनाव हो गए और परिणाम भी आ गया। चुनाव शांति पूर्ण रूप से संपन्न हुए। चुनाव के दौरान जो भी लोग मरे वे लू लगने से मरे। चुनावी ड्यूटी में लगे लोग भी मरे और वोट डालने की लाइन में लगे लोग भी मरे। उनके मरने की हमें चिंता नहीं है। चिंता तो हमें तब होती है जब चुनावी हिंसा में लोग मरते हैं। देश में लू लगने से तो लोग हर साल मरते हैं। बस संतोष यही है कि चुनाव में लोग आपसी लड़ाई में नहीं मरे। आदमी और लू की लड़ाई में आदमी मरे तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आदमी और आदमी की लड़ाई में आदमी नहीं मरने चाहिए। चुनाव के बाद सरकार जी नहीं बदले। सरकार जी वही रहे जो चुनाव से पहले थे। वैसे यह अच्छा ही हुआ। अगर सरकार जी बदलते तो बहुत सारी चीजों को भी बदलना पड़ता। बहुत सारे अफसरों को भी बदलना पड़ता। कुछ अफसर इस्तीफा देते और जो इस्तीफा नहीं देते, वे निकाले जाते। कुछ का तबादला भी होता। कुछ जाते तो कुछ नये भी आते। अगर सरकार जी बदलते तो सबसे ज्यादा दिक्कत ईडी, सीबीआई और आयकर अफसरों को होती। उन्हें तो सिर छिपाने की जगह तक नहीं मिलती। जब अफसर लोग इधर से उधर जाते हैं, उनका तबादला होता है तो देश का बहुत सा पैसा खर्च होता है। अच्छा हुआ, सरकार नहीं बदली और देश का इतना सारा पैसा बच गया। देश के लोग देश का पैसा बचाना चाहते हैं जिससे कि देश के सरकार जी अपने लिए बड़ी कार खरीद सकें, एक बड़ा हवाई जहाज खरीद सकें। सरकार जी अपने रहने के लिए नया मकान बनवा सकें। नया सांसद भवन बनवा सकें। यह सब तो हो गया है तो सरकार जी उस जैसे कई अन्य काम कर सकें। सरकार जी खुद तो बदले ही नहीं, अपने अधिकतर मंत्रियों के मंत्रालय भी नहीं बदले। सरकार जी अपने सभी मंत्रियों के कम काम करने से बहुत खुश जो थे। इसका भी एक बहुत बड़ा लाभ हुआ। अब पुराने लेटर हेड, पुराने नेम प्लेट आदि से ही काम चल जायेगा। इससे भी बहुत बचत होगी। जब एक जिले का, एक शहर का नाम बदलने में ही करोड़ों खर्च हो जाते हैं तो इस काम में कितने खर्च हो जाते, सोचो जरा। सरकार जी बदल जाते तो हम व्यंग्य लिखने वालों को भी मुसीबत आ जाती। दस साल से इन वाले सरकार जी पर ही व्यंग लिखने की आदत पड़ गई है। व्यंग्य लिखते रहे, चार बार कपड़े बदलने पर लेकिन अगर कोई ऐसा आ जाता जो दिन भर एक ही शर्ट में निकाल देता तो? हम व्यंग लिखते रहे दो लाख के चश्मे पर और डेढ़ लाख के पेन पर। कोई इतना खर्चीला न होता तो? दस बीस रुपये के पेन से फ़ाइलें निपटा देता तो? तो हम क्या करते? हम व्यंग्य लिखते रहे, मोर को दाना खिलाने पर। पर दूसरा कोई मोर को दाना न खिलता होता तो? अगर सरकार जी सरकार जी नहीं रहते और कोई दूसरा सरकार जी बन जाता तो? अगर वह ढंग से काम करता तो? वह इतनी नाटकबाजी न करता तो? हमारी तो ऐसी की तैसी हो जाती। व्यंग्य के लिए नये नये टॉपिक ढूंढने पड़ते। अधिक मेहनत करनी पडती।

सरकार जी का सरकार जी बने रहने का लाभ यह है कि नया नहीं लिख पाए तो कुछ फेर बदल कर पुराना ही ठेल दो। अरे सरकार जी भी पुराने ही हैं, काम करने का ढंग भी पुराना ही है। तो व्यंग भी पुराना ही चल जायेगा। हाँ, सरकार जी नहीं बदले हैं तो एक और प्रथा जरूर कायम रहेगी। नेहरू जी की बुराई करने की प्रथा। अब वही सरकार जी हैं तो नेहरू की बुराई करनी ही पड़ेगी। सरकार जी बदल जाते तो नये सरकार जी इन वाले सरकार जी की बुराई करते। दस साल से हो रही नेहरू की बुराई होनी बंद हो जाती। हमारे दस साल से चले आ रहे सरकार जी अब अगले पांच साल और नेहरू की बुराई करेंगे। अब सरकार जी नहीं बदले हैं तो नेहरू की बुराई की प्रथा, हर गलत काम के लिए नेहरू को ही जिम्मेदार ठहराने की प्रथा कायम रहेगी। अब देखो, यह जो नीट का घोटाला है ना, उसके लिए तो नेहरू ही जिम्मेदार हैं। जब अबके सरकार जी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं तो जिम्मेदारी नेहरू की ही तो बनती है। एम्स नेहरू ने ही खोला था ना। और नेहरू ने ही लोगों के दिमाग़ में यह बात डाली कि अच्छे संस्थान खुलने चाहिए और अच्छे संस्थानों से ही से पढ़ना चाहिए। और यह भी कि अच्छे संस्थान से पढ़ना है तो कम्पटीशन देना होगा, अच्छा स्कोर लाना होगा और मेरिट में आना पड़ेगा। नेहरू चाहते तो नियम बना देते, एम्स से एमबीबीएस करना है तो दस करोड़ लगेगा। मौलाना आज़ाद, केजी?मसी (अब केजीएमयू) या उसके बराबर के कॉलेज से करना है तो आठ करोड़ में काम चल जायेगा। कॉलेज उससे कम स्तर का होगा तो कम में भी काम हो जायेगा। पर काम होगा पैसे से ही। लेकिन नेहरू नेहरू थे। उन्होंने नहीं किया। कहा, मेरिट से होगा। मेरिट में आगे हुए तो अधिक अच्छा कॉलेज, पीछे हुए तो कम अच्छा कॉलेज। कौन था उनको रोकने वाला? जो रोकने वाले थे, उस समय वे अल्पमत में थे। पर आज वे बहुमत में हैं। कहते हैं, दाखिला मेरिट कम मीन्स से होगा। मतलब मेरिट से कम, मीन्स से ज्यादा होगा। अच्छे पैसे हों तो अच्छा कॉलेज, नहीं तो ख़राब कॉलेज। साठ लाख में पेपर खरीद लो और मेरिट में स्थान पा जाओ। लेकिन एक दिक्कत हो गई। सिर्फ साठ लाख में पेपर लीक करने से समस्या यह हो गई कि एम्स दिल्ली में एमबीबीएस की जितनी सीटें हैं उससे ज्यादा तो फर्स्ट ही आ गए। उससे ज्यादा तो पूरे बटे पूरे नंबर आ गए, सात सौ बीस में से सात सौ बीस आ गए। लो कर लो बात। एक तरीका है इस समस्या से बचने का। पेपर लीक की कीमत बढ़ा दो। पेपर लीक इतना महंगा कर दो कि उसको बिरला ही खरीद सके। इतना सस्ता पेपर लीक करोगे तो यह समस्या आएगी ही। ठीक है सरकार जी के पास मनमाने कानून बनाने का बहुमत नहीं है। वैसा बहुमत तो नहीं ही है जैसा पिछले दस सालों में था। और पिछले पांच साल जैसा बहुमत तो हरगिज़ ही नहीं है। फिर भी पेपर लीक के बारे में कुछ एक कानून तो बना ही सकते हैं। एक तो पेपर लीक इतना सस्ता नहीं होना चाहिए। नीट का पेपर लीक और वह भी सिर्फ साठ लाख में। इतने में तो चपरासी की नौकरी का पेपर भी लीक नहीं होता है। अरे भई! डाक्टरी में भर्ती की परीक्षा है, थोड़ी तो मर्यादा रखनी चाहिए।

भारतीय मुसलमानों के लिए चुनाव के बाद की वास्तविकताएँ

भारतीय मुसलमानों ने 18वीं लोकसभा के चुनावों में विपक्षी दलों या इंडिया ब्लॉक के लिए काफ़ी समर्थन दिखाया। इस समर्थन ने चरम हिंदुत्व दल को 240 सीटों पर रोकने में अहम भूमिका निभाई, जो सरकार बनाने के लिए ज़रूरी 272 सीटों से कम है। नतीजतन, भाजपा को अब एनडीए सहयोगियों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बने। इससे पहले, भाजपा ने दावा किया था कि वे 400 सीटें जीतेंगे, और उनके कई नेताओं ने संविधान बदलने की धमकी दी थी। नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय मुसलमानों के ख़िलाफ़ कई नफ़रत भरे भाषण दिए। 22 अप्रैल को राजस्थान के बांसवाड़ा में एक ख़ास तौर पर भड़काऊ और ख़तरनाक भाषण में, मोदी ने भारतीय मुसलमानों के ख़िलाफ़ घुसपैठिये शब्द का इस्तेमाल किया, जिसने नरेंद्र मोदी के संभावित तीसरे कार्यकाल के तहत भारतीय मुसलमानों के भविष्य के बारे में गंभीर चिंताएँ पैदा कीं। परिणामस्वरूप, मुसलमानों ने भारतीय संविधान की रक्षा के लिए सार्थक प्रयास किए- अंततः अपने जीवन, आजीविका और घरों को राहुल गांधी की ÷मोहब्बत की दुकान÷ में अपना भविष्य सौंप दिया। चुनाव परिणामों के बाद भी, भारत के सबसे बड़े धार्मिक अल्पसंख्यक मुसलमानों को घृणा अपराधों और हिंसा का शिकार होना पड़ा है। मुस्लिम पुरुषों की भीड़ द्वारा हत्या और मुस्लिम घरों को ध्वस्त करने जैसी कई घटनाएं केंद्र और कई राज्यों में आक्रामक तरीके से सत्ता पर कब्जा करने वाली ताकतों द्वारा दंडात्मक प्रतिशोध के हिस्से के रूप में की गई हैं। संदेश स्पष्ट और जोरदार है- यह उन सभी लोगों के लिए बदला है जिन्होंने हिंदू राष्ट्र का विरोध किया था। छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में चुनाव नतीजों के बाद हिंदुत्ववादी भीड़ और गौरक्षकों ने चार मुस्लिम लोगों की पीट-पीटकर हत्या कर दी। दोनों ही राज्य भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) शासित हैं। भगवाकरण वाले मध्य प्रदेश में अधिकारियों ने संदिग्ध कानूनी बहाने के तहत मुस्लिम घरों को जबरन ढहा दिया। मंडला, जौरा, रतलाम, सिवनी और मुरैना जिलों में दर्जनों मुस्लिम घरों को बुलडोजर से गिरा दिया गया, जिससे परिवार बेघर हो गए और तनाव बढ़ गया, जिससे स्थानीय मुस्लिम आबादी में असुरक्षा की भावना और भी बढ़ गई। हालांकि, कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश में भी, नाहन में एक मुस्लिम व्यक्ति की कपड़ा दुकान में जय श्री राम के नारे लगाने वाली भीड़ ने तोड़फोड़ की, क्योंकि उसने कथित तौर पर बकरीद के बाद व्हाट्सएप परपशु वध की तस्वीर शेयर की थी। स्थानीय कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी संगठनों ने सात मुस्लिम व्यापारियों को 24 घंटे के भीतर अपनी दुकानें खाली करने का अल्टीमेटम दिया और बाजार को बंद करने के लिए मजबूर किया। पुलिस जांच में पता चला कि जानवर गाय नहीं था। मुस्लिम व्यक्ति जावेद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा, तेलंगाना के मेडक में एक और घृणित घटना में (यह राज्य भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस-आईएनसी द्वारा शासित है) मुसलमानों को गोहत्या के झूठे आरोपों पर हिंदुत्ववादी भीड़ द्वारा लक्षित हमलों का सामना करना पड़ा, जिससे समुदाय में व्यापक भय पैदा हो गया और मुस्लिम पुरुष घायल हो गए। इसी तरह, नफ़रत फैलाने वाले भाषण भी बेखौफ जारी हैं। दिल्ली में एक भाजपा नेता ने कथित तौर पर 48 घंटे के भीतर दो लाख मुसलमानों को मारने की धमकी दी है, यह बयान, विशेष रूप से पुलिस की मौजूदगी में दिया गया। यह 27 जून से ही सभी समाचारों में छाया हुआ है। मुसलमानों की चुनावी भागीदारी और योगदान तथा अभियान के दौरान किए गए वादों के बावजूद, भारतीय जनता पार्टी के राजनेता इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर काफी हद तक चुप रहे हैं, जिससे मुस्लिम आबादी खुद को परित्यक्त और असुरक्षित महसूस कर रही है। भारतीय मतदाताओं ने, खास तौर पर हिंदी पट्टी में, भाजपा के नफरत भरे प्रचार को नकार दिया है। दक्षिणपंथी भाजपा ने, राम मंदिर के सफल उद्घाटन के बावजूद, अयोध्या जैसी महत्वपूर्ण सीटों को खो दिया; मुजफ्फरनगर, जो सांप्रदायिक हिंसा के लिए जाना जाता है; और कैराना, जहां एक युवा मुस्लिम महिला इकरा हसन को हिंदू जाटों से पर्याप्त समर्थन मिला। ये चुनावी नतीजे विभाजनकारी राजनीति से बढ़ते मोहभंग और एकता और शांति की इच्छा को दर्शाते हैं। राजस्थान के दुर्गापुर और बांसवाड़ा में मतदाताओं ने नफरत के बजाय एकता को चुना, जहां प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने का प्रयास किया था। मतदाताओं ने विभाजनकारी आख्यानों को नकार दिया, जिसके परिणामस्वरूप इन सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। मतदाताओं, यानी भारत के लोगों से स्पष्ट संकेतों के बावजूद, विपक्षी नेताओं सहित पॉलिटिकल लीडर्स ने इन बढ़ते नफरत भरे अपराधों पर निराशाजनक चुप्पी के साथ प्रतिक्रिया दी है। यह चिंताजनक है, खासकर तब जब मुस्लिम मतदाताओं ने चुनावी नतीजों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विपक्ष के नेता (एलओपी) राहुल गांधी से खास तौर पर अपने ÷मोहब्बत की दुकान÷ अभियान और ÷डरो मत÷ नारे के साथ इस मुद्दे को पर्याप्त रूप से संबोधित करने की उम्मीद की जाती है। उनका अभियान प्यार और साहस को बढ़ावा देता है, फिर भी ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर उनकी चुप्पी इन सकारात्मक संदेशों को नुकसान पहुंचाती है। लक्षित मुस्लिम परिवारों के लिए उनके और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) की ओर से मुखर समर्थन की कमी उनके द्वारा अपनाए गए मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता पर सवाल उठाती है। कई राजनीतिक विश्लेषक इस चुप्पी को एक सनकी चुनावी गणित का नतीजा मानते हैं। पार्टियों को मुस्लिम अधिकारों की जोरदार वकालत करने से दूसरे मतदाताओं को अलग-थलग होने का डर है। यह भावना बताती है कि मुसलमानों के पास सीमित चुनावी विकल्प हैं, जिससे उनके मुद्दों को बिना किसी नतीजे के दरकिनार किया जा सकता है।

विपक्षी नेता प्रतीकात्मक रूप से संविधान को हाथ में लेकर इसके सिद्धांतों के प्रति अपने समर्पण का दावा कर रहे हैं, लेकिन जब भारतीय मुसलमानों की बात आती है तो वे इसे बनाए रखने में विफल रहते हैं। यह पाखंड संविधान द्वारा गारंटीकृत समान अधिकारों और न्याय की नींव को कमजोर करता है, जो बयानबाजी और कार्रवाई के बीच अंतर को उजागर करता है। राजनीतिक चुप्पी के पीछे आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) जैसे समूहों और व्यापक हिंदुत्व एजेंडे का प्रभाव है, जो अल्पसंख्यक अधिकारों पर हिंदू राष्ट्रवाद को प्राथमिकता देता है। इस प्रभाव ने राजनीतिक रणनीतियों में घुसपैठ की है, पार्टियों के भीतर उन आवाज़ों को दबा दिया है जो अल्पसंख्यकों के लिए समावेशी नीतियों और सुरक्षा की वकालत कर सकती हैं। सामुदायिक नेताओं, मानवाधिकार संगठनों और नागरिक समाज समूहों ने हिंसा की निंदा की है और मुस्लिम नागरिकों की सुरक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई का आह्वान किया है। पॉलिटिकल लीडर्स को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए, मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की स्पष्ट रूप से निंदा करनी चाहिए और पीड़ितों के लिए न्याय और अपराधियों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। भारत में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की मौजूदा लहर सिर्फ़ सांप्रदायिक संघर्ष का मुद्दा नहीं है, बल्कि लोकतंत्र और बहुलवाद के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की एक महत्वपूर्ण परीक्षा है। मुसलमान धर्मनिरपेक्षता के लिए वोट करने और नफ़रत के ख़िलाफ़ खड़े होने की कीमत चुका रहे हैं। पॉलिटिकल लीडर्स को चुनावी गणित से ज़्यादा मानवाधिकारों को प्राथमिकता देनी चाहिए, अन्याय के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए और एक ऐसा समाज बनाने की दिशा में काम करना चाहिए, जहाँ हर नागरिक धर्म या जातीयता के आधार पर उत्पीड़न के डर के बिना रह सके। इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर राजनीतिक दलों की चुप्पी भारत के लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों को कमज़ोर करती है और आगे ध्रुवीकरण का जोखिम पैदा करती है। भारत के लोगों ने एकता और सहिष्णुता की अपनी इच्छा का संकेत देते हुए नफ़रत के ख़िलाफ़ जनादेश दिया। यह जनादेश विभाजनकारी राजनीति और सांप्रदायिक हिंसा के ख़िलाफ़ सामूहिक रुख़ को दर्शाता है। पॉलिटिकल लीडर्स को साहस और नैतिक नेतृत्व का प्रदर्शन करके, सभी नागरिकों के अधिकारों के लिए खड़े होकर, उनकी धार्मिक पहचान की परवाह किए बिना इस आह्वान का सम्मान करना चाहिए। तभी भारत एक धर्मनिरपेक्ष और समावेशी लोकतंत्र के रूप में अपने वादे को सही मायने में पूरा कर सकता है।

स्वामी, प्रकाशक वं मुद्रक विजय कुमार ने अशोक सम्राट प्रिन्टर्स, 215, पीरागढ़ी गांव, दिल्ली-87 से मुद्रित कर बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-110086 प्रकाशित किया। सम्पादक : विजय कुमार। (RNI No. 70098/99) इस समाचार पत्र में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी हैं। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगें। Phone : 9810674206

फलस्तीनी इलाके में घुसा इस्राइली नागरिक, गुस्साए लोगों ने कार में लगा दी आग, सामने आया खौफनाक वीडियो

तेल अवीव । इस्राइल और हमास युद्ध के बाद से इस्राइली और फलस्तीनियों के बीच एक दूसरे के प्रति नाराजगी किस कदर बढ़ गई है, इसकी बानगी हाल ही में देखने को मिली। दरअसल एक इस्राइली नागरिक गलती से वेस्ट बैंक में यरुशलम और रामल्लाह के बीच स्थित फलस्तीनी शहर कलंदिया में घुस गया, उसे स्थानीय लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा और लोगों ने इस्राइली नागरिक की कार में आग लगा दी। घटना का वीडियो भी सामने आया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में फलस्तीनियों की भीड़ को इजरायली वाहन का पीछा करते हुए और उस पर पत्थर फेंकते हुए देखा जा सकता है। इस्राइली मीडिया की रिपोर्ट में बताया गया कि कार के चालक ने भागने का प्रयास किया, लेकिन अंततः उसने कार से अपना नियंत्रण खो दिया और एक सैन्य चौकी के पास कंक्रीट के डिवाइडर से टकरा गया। कथित तौर पर उस व्यक्ति को चोटें आईं। कार चालक को बचा लिया गया है और फिलहाल उसका यरुशलम के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस्राइल-हमास युद्ध के बाद से फलस्तीन में इस्राइल के खिलाफ गुस्सा बढ़ा है। फलस्तीनी अधिकारियों की रिपोर्ट के अनुसार, इस्राइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद से वेस्ट बैंक में इस्राइली सेना और इस्राइली नागरिकों के हमले में 553 फलस्तीनियों की मौत हुई है। वहीं फलस्तीनियों के हमले में 15 इस्राइली नागरिकों समेत सैनिक भी मारे गए हैं। वेस्ट बैंक पर 1967 से इस्राइल का कब्जा है। पिछले हफ्ते ही वेस्ट बैंक के जेनिन इलाके में एक हमले में एक इस्राइली सैनिक की मौत की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। इस्राइली सेना भी अक्सर जेनिन इलाके में छापेमारी करती रहती है।

रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का आरोप- सीमा पर आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा अफगान तालिबान

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने रविवार को अफगानिस्तान में तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि बार-बार अनुरोध के बावजूद तालिबान सरकार पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। बीबीसी उर्दू के साथ एक इंटरव्यू में आसिफ ने कहा, पाकिस्तान ने आतंकवादियों को पश्चिमी सीमा की ओर भेजने के लिए 10 अरब रुपये देने की पेशकश की थी और अफगान सरकार से सहयोग की उम्मीद की थी। लेकिन अफगान सरकार आतंकवादियो के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार नहीं थी। पाकिस्तान ने बार-बार अफगानिस्तान की सरकार से कहा है कि वह तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) और अन्य आतंकवादी समूहों को अपनी धरती का इस्तेमाल न करने दे। हालांकि, काबुल भी बार-बार इस दावे को

खारिज करता रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ उसकी जमीन का इस्तेमाल हो रहा है। आसिफ ने कहा कि सरकार ने पश्चिमी सीमा क्षेत्रों में आतंकवादियों को स्थानांतरित करने के लिए 10 अरब रुपये की पेशकश की थी। लेकिन उसे डर था कि आतंकवादी वहां से भी पाकिस्तानी की सीमा में लौट सकते हैं। पिछले हफ्ते वॉयस ऑफ अमेरिका को दिए इंटरव्य में आसिफ ने कहा था कि सैन्य अभियान अज्म-ए-इस्तेकाम के तहत पाकिस्तान सीमा पार अफगानिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को निशाना बना सकता है। उन्होंने टीटीपी के साथ बातचीत की संभावना को भी खारिज कर दिया था। इस साल मार्च में पाकिस्तानी वायु सेना के लड़ाकू विमानों ने अफगानिस्तान के अंदर खोस्त और पक्तिका के सीमावर्ती क्षेत्रों में आतंकवादियों के खिलाफ हवाई हमले किए थे। इन हवाई हमलों के तुरंत बाद आसिफ ने कहा था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को बताना चाहता है कि हम पाकिस्तान में इस तरह के आतंकवादी हमलों जारी नहीं रहने दे सकते। इस्लामाबाद ने यह कार्रवाई तब की थी जब पाकिस्तानी बलों पर एक घातक आतंकी हमला हुआ। इस हमले में एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक कैप्टन सहित सात सैनिक मारे गए। अगस्त 2021 में अमेरिका के जाने के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान में सरकार बना ली। इसके बाद से पाकिस्तान में आतंकवाद की घटनाओं में भारी बढ़ोतरी हुई। इससे इस्लामाबाद की उम्मीदें टूट गईं कि अफगानिस्तान में दोस्ताना सरकार आतंकवाद से निपटने में उसकी मदद करेगी। एक थिंक टैंक %सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान में 2023 में 789 आतंकवादी हमले हुए। आतंकवाद रोधी अभियानों में 1524 लोगों की मौत हुई।

दक्षिणपंथियों की बढ़ती ताकत के बीच फ्रांस में चुनाव, सत्ता में बदलाव के संकेत; मैक्रों की साख दांव पर

पेरिस । फ्रांस में संसदीय चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है। इस चुनाव को बहुमत की आस लगाए बैठे राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के लिए एक परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। मैक्रों के गठबंधन को वामपंथी गठबंधन से मजबूत चुनौती मिल रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देश में पहली दक्षिणपंथी सरकार बन सकती है, जो यूरोपीय संघ में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। इस महीने की शुरुआत में छह जून को यूरोपीय संसद के लिए चुनाव हुए थे। इस दौरान फ्रांस में सबसे चौंकाने वाली राजनीतिक परिस्थितियां थीं। यहां फ्रांस की धुर दक्षिणपंथी नेता मरीन ला पेन की नेशनल रैली ने मैक्रों की पार्टी को जबरदस्त झटका दिया था। इसके बाद ही राष्ट्रपति ने अंतिम नतीजे आने से पहले ही अचानक राष्ट्रीय चुनावों की घोषणा कर सबको हैरान कर दिया था। उन्होंने कहा था, मैंने फैसला किया है कि आप वोट के जरिए अपना संसदीय भविष्य चुने। इसलिए मैं नेशनल असेंबली भंग कर रहा हूं। धुर दक्षिणपंथी पार्टियां हर तरफ आगे बढ़ रही हैं। यह ऐसे हालात हैं, जिन्हे मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मरीन ले पेन की नेशनल रैली लंबे समय से राजनीतिक गलियारों से बाहर थी, लेकिन अब वह पहले से कहीं ज्यादा सत्ता के करीब है। ऐसे में 30 जून और सात जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय चुनाव हो रहे हैं। मध्य जुलाई तक यह साफ हो जाएगा कि राजनीतिक समीकरणों में मैक्रों की स्थिति क्या रहती है और क्या उन्हें एक धुर दक्षिणपंथी प्रधानमंत्री के साथ मिलकर सत्ता चलाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हालांकि, केवल दो साल पहले राष्ट्रपति पद की दूसरी पारी संभालने वाले मैक्रों के अपने पद के लिए इन चुनावों से कोई अंतर पैदा नहीं होगा क्योंकि राष्ट्रपति चुनावों में अभी वक्त है और वह अपना तीन साल का बचा हुआ कार्यकाल पूरा करेंगे। फ्रांस में भारतीय समयानुसार सुबह साढ़े 11 बजे से रात में साढ़े नौ बजे तक मतदान होगा। एग्जिट पोल देर रात सामने आ सकता है। वहीं, एक हफ्ते बाद दूसरे चरण के लिए वोटिंग होगी। हालांकि, 577 सीटों वाली नेशनल असेंबली में सीटों के सटीक बंटवारे का अनुमान लगाना कठिन हो सकता है।

अपने बेटे बैरन को लेकर मेलानिया ने पति ट्रंप से किया बड़ा समझौता, अगर वह राष्ट्रपति बने तो....

वॉशिंगटन । अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। इसके लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप जमकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं, उन्हें डेमोक्रेट के उम्मीदवार और मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडन से कड़ी टक्कर मिल रही है। इस बीच एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर 78 साल के ट्रंप राष्ट्रपति बन जाते हैं, तो वह अपनी पत्नी मेलानिया को कुछ खास सक्रिय नहीं देख पाएंगे। दरअसल, मेलानिया ने पूर्व राष्ट्रपति से एक समझौता किया है। उन्होंने अपने पति से कहा, अगर आप चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बनते हैं, तो मुझे 24 घंटे प्रथम महिला के तौर पर सक्रिय नहीं रहना पड़ेगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पूर्व प्रथम लेडी ने यह समझौता इसलिए किया है क्योंकि वह अधिक से अधिक समय अपने बेटे बैरन के साथ बिताना चाहती हैं। 18 साल के बैरन जल्द ही न्यूयॉर्क शहर के एक विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए चले जाएंगे। सूत्रों का कहना है कि वह एक मां हैं और अपने बेटे के

साथ हर महीने कुछ समय बिताने की योजना बना रही हैं। यहां तक कि वह न्यूयॉर्क में हर हफ्ते अपने बेटे से मिल सकती हैं। बैरन को ट्रंप परिवार ने अब तक सुर्खियों से दूर रखा है। बैरन का जन्म मार्च 2006 में हुआ था और वह डोनाल्ड ट्रंप की पांचवीं और मेलानिया ट्रंप की पहली संतान हैं। बैरन का बचपन न्यूयॉर्क में बीता है और उनकी शुरुआती पढ़ाई भी वहीं से हुई है। जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए थो तो उन्होंने बताया था कि बैरन न्यूयॉर्क छोड़कर व्हाइट हाउस जाने में झिझक रहे थे। बैरन अभी 18 साल के हैं। सूत्रों ने आगे कहा, बैरन पहले कभी पूरी तरह से अकेले नहीं रहे हैं। अब कॉलेज में वह प्रवेश लेने वाले हैं। ऐसे में कुछ चिंताओं से बचाने के लिए मेलानिया अपने बेटे के करीब रहना चाहती हैं। अगर ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं तो बैरन को मिलने वाला समय बंट जाएगा, जिससे वह परेशान हो सकता है। मेलानिया अपने बच्चों को लेकर बहुत भावुक हैं। वह उनकी सुरक्षा को लेकर हमेशा सतर्क रहती हैं। वह पहले ही इस बात से भी इनकार कर चुकी हैं कि बैरन फ्लोरिडा से रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में रिपब्लिकन प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे।

ब्रिटिश पीएम सुनक का भारत से खास नाता, हिंदू धर्म में रखते है आस्था

लंदन । ब्रिटेन में चार जुलाई को आम चुनाव के लिए मतदान होगा। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हैं। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को कीर स्टर्मर की लेबर पार्टी से एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इन चुनावों के बीच पिछले चुनाव की याद आ जाती है, जब यूनाइटेड किंगडम में एक अलग ही इतिहास रचा गया था। साल 2022 में 25 अक्तूबर को सुनक पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री बने। वह पहले ऐसे भारतवंशी हैं, जो ब्रिटेन में इतने बड़े पद पर पहुंचे हैं। इससे भारत और ब्रिटेन के रिश्ते में और अधिक सुधार हुआ। हालांकि, इन चुनावों में अब पीएम सुनक के सामने कड़ी चुनौती बनी हुई है। ऋषि सुनक का जन्म 12 मई 1980 को ब्रिटेन के साउथम्पटन में हुआ था। उनके पिता यशवीर सुनक डॉक्टर और मां उषा सुनक एक क्लीनिक चलाती थीं। उनके माता-पिता 1960 के दशक के दौरान पूर्वी अफ्रीका से ब्रिटेन चले गए थे। ऋषि के दादा-दादी का जन्म पंजाब प्रांत (ब्रिटिश इंडिया) में हुआ था। इस लिहाज से ऋषि की जड़ें भारत से जुड़ी हुई हैं। ऋषि तीन बहन-भाई में सबसे बड़े हैं। ऋषि के पिता केन्या और मां तंजानिया से हैं। ऋषि ने राजनीतिक विज्ञान की पढ़ाई ब्रिटेन के विंचेस्टर कॉलेज से की है। इसके बाद वह आगे की पढ़ाई के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले

गए थे। ऋषि ने फिलोसॉफी, इकॉनोमिक्स और एमबीए की पढ़ाई की है। सुनक ने इंफोसिस प्रमुख नारायण मूर्ति और राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति से शादी की। इन दोनों की मुलाकात स्टैनफोर्ड में एमबीए कोर्स के दौरान हुई थी। ऋषि और अक्षता की दो बेटियां कृष्णा और अनुष्का हैं। साल 2015 में वह पहली बार यूके की संसद में पहुंचे थे। उन्होंने रिचमंड (यॉर्क) से संसद सदस्य के रूप में काम किया। उन्हें यूके के सबसे अमीर सांसदों में से एक माना जाता है। वह ब्रेग्जिट का समर्थन करते थे, इस वजह से राजनीति में वह तेजी से आगे बढ़ने लगे। वह साल 2019 में बोरिस सरकार में ब्रिटेन के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। ऋषि सुनक हिंदू धर्म को मानते हैं और कृष्ण भक्त हैं। सांसद बनने के दौरान उन्होंने ब्रिटिश संसद यानी ऑफ कामंस में भगवत गीता से ही शपथ ली थी।

सर्बिया में इस्राइली दूतावास पर हमला, ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी को बनाया निशाना; हमलावर ढेर

बेलग्रेड । सर्बिया के एक पुलिस अधिकारी ने शनिवार को एक व्यक्ति को मार गिराया। व्यक्ति ने बेलग्रेड में इजरायली दूतावास के सामने क्रॉसबो से उसकी गर्दन पर गोली चलाई थी। वहीं सर्बिया की प्रधानमंत्री ने इसे आतंकवादी हरकत बताया है। सर्बिया की राजधानी में सुबह लगभग 11 बजे एक हमलावार ने इजरायली दूतावास के बाहर ड्यूटी पर तैनात अधिकारी को गोली मार दी।

इसके बाद पुलिसकर्मी ने भी हमलावर पर गोली चलाई। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आंतरिक मंत्री इंविका डेसिक ने कहा कि पुलिसकर्मी ने आत्मरक्षा में गोली चलाई थी। 34 वर्षीय अधिकारी हमले के समय अपने गार्ड बूथ में थे। उनकी अस्पताल में सर्जरी हुई। पुलिस पर हमला करने वाला व्यक्ति बेलग्रेड से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित म्लादेनोवैक शहर का है। उसने इस्लाम धर्म में खुद को परिवर्तित किया है। अधिकारियों के अनुसार हमलावर नोवी पज़ार में रहने के लिए चला गया था, जो

सर्बिया में बोस्नियाक मुस्लिम अल्पसंख्यक का ऐतिहासिक और राजनीतिक केंद्र है। यह देश में इस्लाम का केंद्र है।

पुलिस का कहना है कि सुरक्षा सेवाओं को कुछ लोगों पर हमले से जुड़े होने का संदेह था, इसलिए कुछ गिरफ्तारी की गई थी। उसमें बेलग्रेड का एक व्यक्ति भी शामिल है। जिसे दो वर्ष पहले भी कई आतंकवादी इंटरनेट साइट जो कि जिहाद का आह्वान करती थी, वह उन्हें ऑपरेट करता था। इस कारण उसे गिरफ्तार किया गया था। हालांकि बाद में उसे गिरफ्तार कर दिया गया था। पुलिस का कहना है कि वे कई स्थानों पर तलाशी ले रहे हैं।

आतिशी ने चंद्रावल जल शोधन संयंत्र का निरीक्षण किया, कहा- जल्द ही जलापूर्ति सामान्य हो जाएगी

नयी दिल्ली।

दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने रविवार को अधिकारियों को चंद्रावल जल उपचार संयंत्र के पंप हाउस की मरम्मत करने का निर्देश दिया, जहां भारी बारिश के कारण पानी भर गया था और यह सुनिश्चित किया गया कि ऐसी समस्या फिर न हो। चंद्रावल जल उपचार संयंत्र का निरीक्षण करने के बाद एक्स पर हिंदी में लिखे एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि अप्रत्याशित बारिश के कारण चंद्रावल जल उपचार संयंत्र के पंपिंग हाउस में पानी भर गया, जिससे मोटरें क्षतिग्रस्त हो गईं। आतिशी ने कहा, इसके कारण मध्य दिल्ली के कई हिस्सों में पानी की आपूर्ति बाधित हुई। जल बोर्ड ने इस समस्या को हल करने के लिए तेजी से काम किया है और प्लांट की लगभग 80 प्रतिशत मरम्मत कर दी गई है।

जल्द ही पानी की आपूर्ति सामान्य हो जाएगी। उन्होंने कहा, आज प्लांट का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जल्द से जल्द पंप हाउस की मरम्मत करने का आदेश दिया तथा संयुक्त निरीक्षण के साथ यह सुनिश्चित करने को कहा कि भविष्य में किसी भी प्लांट में यह समस्या दोबारा न आए। राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार की सुबह भारी बारिश हुई, क्योंकि मानसून के पहले दिन 228.1 मिमी बारिश हुई, जो 1936 के बाद से जून महीने में सबसे अधिक है। इससे शहर के कई हिस्से जलमग्न हो गए और कई लोगों की जान चली गई। आईएमडी ने दिल्ली में भारी बारिश का अनुमान जताया है और शहर को 2 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट पर रखा है।

भारी बारिश से दिल्ली पानी-पानी, नगर निकायों ने जलभराव से निपटने की तेज की तैयारियां

नई दिल्ली । दिल्ली में मंगलवार तक भारी बारिश के पूर्वानुमान के बीच नगर निकायों ने जलभराव की समस्या से निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं जिसके तहत कर्मचारियों और उपकरणों की तैनाती बढ़ाने समेत क्षेत्रीय इकाइयों को सतर्क रखने के कदम उठाए गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी में मानसून आगमन के पहले दिन शुक्रवार की सुबह 228.1 मिलीमीटर बारिश हुई, जो 1936 के बाद जून माह में अब तक की सर्वाधिक वर्षा है। बारिश से शहर के कई हिस्सों में जलभराव हो गया और कई लोगों की जान चली गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने दिल्ली में 'ओरेंज अलर्ट जारी करते हुए 2 जुलाई तक भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) के एक अधिकारी ने कहा कि नगर निकाय ने जलभराव की शिकायतों से निपटने के लिए कर्मचारियों की तैनाती बढ़ा दी है और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से लुटियंस दिल्ली के अंतर्गत आने वाले इलाकों में निगरानी कर रहा है। कई सांसदों के बंगलों में शुक्रवार को पानी घुसने के साथ लुटियंस दिल्ली के इलाके में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए थे। एनडीएमसी के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा कि उन्होंने गोल्फ लिंक्स और भारती नगर में चार अतिरिक्त पंप तैनात किए हैं, जहां शुक्रवार को अत्यधिक जलभराव हुआ था। उन्होंने कहा, तीन 'सुपर सक्शन मशीन से युक्त वाहन संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त करते रहेंगे। हमने अतिरिक्त कर्मचारियों को भी तैनात किया है और सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। उपाध्याय ने 'पीटीआई-भाषा से कहा, प्रत्येक संवेदनशील क्षेत्र को एक अधीक्षण अभियंता के अधीन रखा गया है, एनडीएमसी केंद्रीय कमान और नियंत्रण कक्ष सीसीटीवी कैमरों के जरिए सभी संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी करेंगे। नगर निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उनका केंद्रीय नियंत्रण कक्ष 24 घंटे काम कर रहा है और दावा किया कि नालों से गाद निकालने का काम पूरा हो चुका है। जोनल नियंत्रण कक्षों के माध्यम से मिल रही जलभराव की सूचनाओं पर विभिन्न मशीने तैनात की गई है।

प्रधानमंत्री मोदी ने 'मन की बात' में जनता के मुद्दों का उल्लेख नहीं किया : पवन खेड़ा

नयी दिल्ली। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने रविवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' में उन मुद्दों का जिक्र नहीं किया, जिनके बारे में लोग सुनना चाहते थे। प्रधानमंत्री द्वारा अपने तीसरे कार्यकाल में पहली बार 'मन की बात' कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद उन पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार प्रमुख खेड़ा ने सवाल किया कि उन्होंने नीट, रेल दुर्घटना या बुनियादी ढांचों के गिरने का उल्लेख क्यों नहीं किया। खेड़ा ने कहा कि भले ही यह मोदी का तीसरा कार्यकाल है, लेकिन यह उनके अपने बल पर नहीं है।

खेड़ा ने कहा, सरकार बैसाखियों पर चल रही है। हमें लगा कि इस बार वह कुछ समझदारी वाली बात कहेंगे। खेड़ा ने कहा, उन्होंने (मोदी ने) नीट, रेलवे दुर्घटना या आए दिन होने वाली बुनियादी ढांचों के गिरने की घटनाओं के बारे में कुछ नहीं कहा, जिसके बारे में हम सुन रहे हैं। खेड़ा ने कहा, ''उन्होंने दिल्ली हवाईअड्डे पर हुई गंभीर घटना पर कुछ नहीं कहा, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई।'' उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने लोगों से जुड़े किसी मुद्दे पर कुछ नहीं कहा। उन्होंने आरोप लगाया, प्रधानमंत्री ने लोगों के हित से जुड़े किसी मुद्दे पर बात नहीं की। उनका तरीका एजेंडा बदलने का रहा है, क्योंकि हर कोई नीट, घोटालों के बारे में बात कर रहा है, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए आप केरल से छाता लाने की बात कर रहे हैं...। उन्होंने कहा, चुनावों के दौरान आप उत्तर को दक्षिण के खिलाफ खड़ा कर रहे थे... क्या आपको लगता है कि लोग भूल जाएंगे? आप प्रचार के दौरान जो कहते हैं वह सच है, अब आप जो कर रहे हैं, वह दुष्प्रचार है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तीसरी बार देश की कमान संभालने के बाद अपने पहले 'मन की बात' रेडियो कार्यक्रम में रविवार को कहा कि लोगों ने दुनिया के सबसे बड़े चुनाव में देश के संविधान और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपना अटूट विश्वास व्यक्त किया है। इन चुनावों में 65 करोड़ लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया।

जय फलस्तीन पर बवाल: हिंदू सगंठनों ने ओवैसी के खिलाफ खोला मोर्चा, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प

दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की थी। दोनों संगठनों के सदस्यों ने बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़कर नारेबाजी की।

नई दिल्ली । दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के सदस्यों ने संसद में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जय फलस्तीन नारे को लेकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान दोनों संगठनों के सदस्यों ने जमकर नारेबाजी की। बताया जा रहा है कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई है। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की थी। दोनों संगठनों के सदस्यों ने बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़कर नारेबाजी की। उनके हाथों में ओवैसी की आपत्तिजनक तस्वीरें भी देखी गई हैं। 25 जून को संसद में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान तेलंगाना के हैदराबाद से एक बार फिर चुनकर सांसद बने असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में अपने शपथग्रहण से नए विवाद को जन्म दे दिया। दरअसल, ओवैसी ने शपथ लेने के आखिर में फलस्तीन के समर्थन में नारा लगाया। इसे लेकर सत्तापक्ष के सांसदों ने विरोध दर्ज कराया। बाद में सभापति ने इसे रिकॉर्ड से हटाने का निर्देश दिया। ओवैसी ने इस बयान को लेकर बाद में पत्रकारों से कहा, जो मैंने कहा वो आपके सामने है। सब बोल रहे हैं। क्या नहीं बोले। ये किसके खिलाफ है आखिर। बताइए संविधान का कौन सा प्रोविजन है। जो लोग विरोध करते हैं, उनका काम ही वही है। छोड़िए, अब क्या कर सकते हैं।

दिल्ली सरकार के फंड से चलने वाले 12 कॉलेजों में भी उठी शिक्षक भर्ती की मांग, अभी इतने पद हैं खाली

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार से पूर्ण वित्त पोषित 12 कॉलेजों में अभी तक चार में दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज , आचार्य नरेंद्रदेव, भाष्कराचार्य कॉलेज ऑफ एप्लाइड साइंस व अदिति महाविद्यालय ने अपने यहां सहायक प्रोफेसर के पदों के विज्ञापन निकाले हैं। बाकी आठ कॉलेजों ने अभी तक शिक्षकों के पदों को भरने संबंधी विज्ञापन न निकाले जाने के कारण वहां पढ़ा रहे एड हॉक शिक्षकों में गहरा रोष व्याप्त है। उनका कहना है कि वे पिछले एक दशक से पढ़ा रहे हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकांश कालेजों में 80 फीसदी शिक्षकों के पद भरे जा चुके हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने अभी तक अपने यहां स्थायी सहायक प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू नहीं की। इन कॉलेजों में लगभग 600 शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति की जानी है। फोरम ऑफ एकेडेमिक्स फार सोशल जस्टिस ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह को पत्र लिखकर मांग की है कि दिल्ली सरकार से पूर्ण वित्त पोषित 12 कॉलेजों में भी सहायक प्रोफेसर के पदों पर जल्द से जल्द स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कराएं। ताकि विश्वविद्यालय से तदर्थवाद समाप्त हो और इन कालेजों के शिक्षकों में भी स्थायित्व हो। 12 कॉलेज में रिक्त 600 पद जल्द से जल्द भरे जाने चाहिए।

जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने संभाला नए सेना प्रमुख का कार्यभार, जनरल मनोज पांडे हुए रिटायर

नई दिल्ली। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने रविवार को 30वें सेना प्रमुख का पदभार संभाला. उन्होंने जनरल मनोज पांडे का स्थान लिया है. जनरल द्विवेदी को चीन और पाकिस्तान से सटी सीमाओं पर कार्य करने का व्यापक अनुभव है. वह उप सेना प्रमुख के रूप में भी काम कर चुके हैं. जनरल द्विवेदी 19 फरवरी को सेना के उप प्रमुख का कार्यभार संभालने से पहले 2022-2024 तक उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ रहे थे. उन्होंने 13 लाख जवानों वाली सेना की कमान ऐसे समय में संभाली है जब भारत चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चुनौतियों समेत कई सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है. सेना प्रमुख के तौर पर, उन्हें एकीकृत कमान शुरू करने की सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पर नौसेना और भारतीय वायु सेना के साथ भी तालमेल बनाना पड़ेगा. रीवा के सैनिक स्कूल के छात्र रहे जनरल द्विवेदी 15 दिसंबर 1984 को भारतीय सेना की 18जम्मू कश्मीर राइफल्स में शामिल हुए थे. उन्होंने बाद में इस इकाई की कमान भी संभाली. करीब 40 साल के अपने लंबे और आसाधारण करियर में वह विभिन्न पदों पर रहे. उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक तथा अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है. अधिकारियों ने बताया कि उत्तरी सेना के कमांडर के तौर पर जनरल द्विवेदी ने जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद रोधी अभियानों के संचालन के अलावा, उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर अभियान के संचालन की योजना और कार्यान्वयन के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन और परिचालन संबंधी अंतर्दृष्टि प्रदान की है. उन्होंने बताया कि इस दौरान जनरल द्विवेदी सीमा विवाद को हल करने में चीन के साथ जारी वार्ता में सक्रिय रूप से शामिल रहे. वह भारतीय सेना की सबसे बड़ी सैन्य कमान के आधुनिकीकरण में भी शामिल रहे. उन्होंने 'आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी हथियारों को अपनाने के अभियान का नेतृत्व किया. सैनिक स्कूल रीवा, नेशनल डिफेंस कॉलेज और यूएस आर्मी वॉर कॉलेज के पूर्व छात्र लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने डीएसएससी वेलिंगटन और आर्मी वॉर कॉलेज, महू में भी अध्ययन किया है. लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को लेकर अग्रणी रहे हैं. उन्होंने सेना की नॉर्दर्न कमांड में तकनीक को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. इसके साथ ही नए सेनाध्यक्ष आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, बिग डेटा एनालिटिक्स, क्वांटम जैसी आधुनिकतम तकनीक के इस्तेमाल की दिशा में भी काम करते रहे हैं. वह सोमालिया में रहे और सेशेल्स सरकार के सैन्य सलाहकार के रूप में काम किया. इसके साथ ही भारतीय सेना में पहली बार एक साथ पढ़ चुके दो अधिकारी सेना की दो अलग-अलग शाखाओं का नेतृत्व कर रहे हैं.

दरअसल लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी और भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी क्लासमेट रह चुके हैं.

हरिद्वार-मथुरा के बाद खाटू श्याम से जुड़ा कुरुक्षेत्र, धर्म नगरी से मंत्री सुभाष सुधा ने बस को दिखाई हरी झंडी

कुरुक्षेत्र । धर्म नगरी कुरुक्षेत्र के लोगों के लिए खुशखबरी है। सनातन धर्म को मानने वालों के लिए अब खाटू श्याम जाने के लिए कुरुक्षेत्र से रोडवेज बस चलेगी। राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने रविवार को कुरुक्षेत्र से खाटू श्याम को जाने वाली हरियाणा रोडवेज बस को मंत्री सुभाष सुधा ने हरी झंडी दिखा कर रवाना किया। इस दौरान राज्यमंत्री ने बस में सवार होकर खाटू श्याम का नारा लगाकर श्रद्धालुओं को बस की सौगात मिलने पर बधाई दी। गौरतलब है कि पहले ही धर्म नगरी कुरुक्षेत्र को भगवान श्रीकृष्ण के नगर मथुरा से जोड़ा जा चुका है।

पहले धर्म नगरी कुरुक्षेत्र भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा और हरिद्वार से जुड़ चुका है। अब बाबा खाटू श्याम बाबा खाटू श्याम की नगरी खाटू श्याम भी बस जाएगी। वहीं हरियाणा प्रदेश के स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि मानसून का मौसम चल रहा है, ऐसे में प्रदेश के अधिकारी एसी में ना बैठकर फील्ड में निकलें। किसी भी कीमत पर लापवाही बरतने वाले अधिकारी को तुरन्त सस्पेंड किया जाएगा। अभी गुरुग्राम,फरीदबाद, अम्बाला में कई अधिकारी सस्पेंड भी किये जा चुके हैं। कुरुक्षेत्र नए बस स्टैंड से यह बस सुबह 8.30 बजे चलेगी और 152डी से होते हुए खाटू श्याम सायं 4 बजे पहुंचेगी। इस का किराया मात्र 435 निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में हैप्पी कार्ड योजना भी चलाई गई है। जिसके माध्यम से संबंधित लाभार्थी वर्ष में 1 हजार किलोमीटर निःशुल्क यात्रा कर सकता है। हैप्पी कार्ड योजना से लाभार्थियों को काफी फायदा मिल रहा है। राज्यमंत्री ने सिटी बस की सौगात देते हुए कहा कि आरडब्ल्यूए व विद्यार्थियों की मांग पर नए स्टैंड से यह बस सेवा शुरु की गई है। यह बस नए बस स्टैंड से चलेगी और सेक्टर-13, 8, 7, 5, 4, 3, 2 से होते हुए उमरी चौक पहुंचेंगी। यह बस प्रत्येक घंटे नए बस स्टैंड से यात्रियों के लिए उपलब्ध रहेगी।

एन्हांसमेंट वसूली पर पूर्व सीएम हुड्डा ने सरकार को घेरा, कहा- कांग्रेस सत्ता में आई तो करेंगे विचार

चंडीगढ़ । पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शहरवासियों से बार-बार हो रही एन्हांसमेंट वसूली पर कहा कि पहले से ही मंदी, महंगाई और बेरोजगारी का दंश झेल रही जनता पर पड़ रहे बोझ को लेकर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। भाजपा लगातार जनता के इस दर्द को अनदेखा कर रही है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर शहरवासियों की मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा। शनिवार को बहादुरगढ़ सेक्टर 2, 9 और 9ए के निवासी हुड्डा को एक ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे। व्यापारियों से कानून व्यवस्था पर बातचीत में हुड्डा ने बढ़ते अपराध पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में बेकाबू अपराध के चलते आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है। फायरिंग, फिरौती, लूट, डकैती, हत्या और रेप जैसी वारदात लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन गई हैं। सिर्फ 4 दिन के भीतर अकेले हिसार में 3 व्यापारियों से 9 करोड़ की रंगदारी मांगने की वारदातें हो चुकी हैं। लेकिन अपनी जिम्मेदारी को निभाने में भाजपा पूरी तरह विफल साबित हुई है।

जो सरकार नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे सकती, उसे सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर अपराध का सफाया करके हरियाणा को फिर से सुरक्षित राज्य बनाया जाएगा। छात्र संसद के प्रतिष्ठित 'इंटरनेशनल लीडरशिप टूर-24' के प्रतिनिधियों ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा से मुलाकात की। देश भर के प्रमुख संस्थानों जैसे आईआईटी, आईआईएम, एनएलयू और विभिन्न निजी विश्वविद्यालयों से चुने गए प्रतिनिधियों ने भारतीय लोकतंत्र के भविष्य को लेकर हुड्डा के साथ चर्चा की। बातचीत के दौरान हुड्डा ने विपक्ष की मजबूती, विपक्ष के तौर पर इंडिया गठबंधन की भूमिका के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि एक मजबूत विपक्ष स्वस्थ लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण होता है और लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी बेहद जरूरी है।

सूरजभान कटारिया ने प्रधानमंत्री गृहमंत्री व मंत्री को वास्तविक स्थिति देश को बताने के लिए लिखा पत्र

चंडीगढ़ । देश की राजधानी स्थित नए बनाए गए संसद भवन में संसदीय परंपरा से लोकसभा एवं राज्यसभा कार्रवाई आरंभ हैं। पूर्व का संसद भवन अब संविधान भवन के रूप में देश को समर्पित किया गया है। पुरानी संसद भवन से संविधान निर्माता बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विशाल प्रतिमाओं को नए संसद भवन में स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित है। विपक्षी नेता राहुल गांधी के साथ देश भर के अंबेडकरवादी और गांधीवादी इन प्रतिमाओं को स्थानांतरित किए जाने पर विस्तृत जानकारी के अभाव से देश को गुमराह करने वाले बयानबाजी कर रहे हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अधीन डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन के पूर्व सदस्य रहे सूरजभान कटारिया ने इस सारे संवेदनशील विषय पर देश के प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री को पत्र लिखकर वास्तविक स्थिति देश को अवगत कराने का आग्रह किया है। कटारिया का स्पष्ट कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अन्य महापुरुषों के साथ-साथ बाबा साहब अंबेडकर को कई मामलों में सम्मान देने का कार्य किया है जिनमें उनके जन्मभूमि, महू (मध्य प्रदेश), दीक्षाभूमि, नागपुर (महाराष्ट्र), महापरिनिर्वाण भूमि 26 अलीपुर रोड (दिल्ली) और संस्कार भूमि, दादर (मुंबई) के साथ ही लंदन स्थित उनकी शिक्षा भूमि को पंचतीर्थ के रूप में देश को समर्पित करके बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। उल्लेखनीय है कि पिछले लगभग 1 माह से पुराने संसद भवन से नई संसद भवन में स्थानांतरित बाबा साहब अंबेडकर महात्मा गांधी आदि की प्रतिमाओं का विषय देशभर में चर्चा का विषय बना है कहीं संगठन इस विषय पर धरना प्रदर्शन आदि भी कर रहे हैं। कटारिया का कहना है कि इस पर वास्तविक स्थिति की जानकारी देश के सामने आनी अति आवश्यक है।

हरियाणा में मानसून का आगमन, बाढ़ रोकथाम की तैयारियां अधूरी; अब भी 23 फीसदी ड्रेनें साफ नहीं

चंडीगढ़ । हरियाणा में मानसून का आगमन हो गया है, मगर बाढ़ की रोकथाम की तैयारियां पूरी नहीं हो सकीं। हरियाणा में 28 जून तक करीब 77 फीसदी ड्रेन ही साफ हो सकी थीं। बाकी 23 फीसदी ड्रेनों की सफाई नहीं हो पाई। कुछ जगहों पर अब भी काम बाकी है। हालांकि सरकार ने 30 जून तक बाढ़ की पूरी तैयारियां करने का निर्देश दिया था। सिंचाई मंत्री अभय सिंह यादव ने कहा कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार की स्थिति काफी बेहतर है। उन्होंने खुद तैयारियों का जायजा लिया है। जहां काम रहते हैं, वह भी जल्द पूरे हो जाएंगे। पिछले साल हरियाणा में बाढ़ ने काफी कहर बरपाया था। जगह-जगह जलभराव की स्थिति बन गई थी। करीब 44 लोगों ने बाढ़ की चपेट में आकर दम तोड़ दिया था। हजारों लोग बेघर हो गए थे। हरियाणा के 22 जिलों में कुल 673 ड्रेन हैं, जिनकी

कुल लंबाई 4212.69 किलोमीटर है। सिंचाई विभाग का दावा है कि करीब 3253.46 किलोमीटर तक ड्रेनों की सफाई की जा चुकी है। बाकी बची ड्रेनों की सफाई का काम जारी है। उन्हें भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही सभी जिलों के हॉटस्पॉट चिह्नित कर अस्थायी सुरक्षा के उपाय कर दिए गए हैं। सभी महत्वपूर्ण स्थलों पर सीमेंटेड बैग, बल्ली और मोबाइल पंप रखे गए हैं। जलभराव की स्थिति में सिंचाई विभाग ने 2342 मोबाइल पंप की व्यवस्था की है। इन पंपों की क्षमता 7610 क्यूसेक है।

पिछले साल आई बाढ़ से सबक लेते हुए सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक में बाढ़ की रोकथाम के लिए सिंचाई विभाग की 617 योजनाओं के लिए 1279 करोड़ रुपये अलॉट हुए थे। इनमें सबसे अधिक योजनाएं उन जिलों के लिए थीं, जो पिछले साल बाढ़ की चपेट में आए थे। इसी बैठक में बाढ़ को रोकने के लिए 320 अल्पावधि की योजनाएं भी विभिन्न जिलों में प्रस्तावित की गई थीं, जिनमें से सिर्फ 74 स्कीम ही पूरी हो सकी हैं, जबकि 246 योजनाओं पर काम जारी है। सिंचाई विभाग के मुताबिक यमुनानगर की 76 योजनाओं के लिए 118.79 करोड़, झज्जर की 67 योजनाओं के लिए 115.01 करोड़, अंबाला की 53 योजनाओं के लिए 77.83 करोड़, सोनीपत की 44 योजनाओं के लिए 133 करोड़, कैथल की 43 योजनाओं के लिए 69 करोड़, पंचकूला की 42 योजनाओं के लिए 22.94 करोड़, रोहतक की 36 योजनाओं के लिए 79 करोड़ और फतेहाबाद की 27 योजनाओं के लिए 60 करोड़ रुपये अलॉट किए गए थे।

विजिलेंस का फेलियर : करोड़ों के सफाई घोटाले के जिस आरोपी को ढूंढ रही टीमें, वह बीजेपी नेताओं संग ले रहा सेल्फी

कैथल । जिला परिषद में हुए 7 करोड़ रुपये के सफाई घोटाले की जांच कर रही एंटी करप्शन ब्यूरो टीम की कार्यशैली पर अब सवाल उठने लगे हैं। इस घोटाले में कुल 14 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, इनमें से अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इस एफ.आई.आर में शहर के एक बड़े भाजपा के नेता का नाम भी शामिल है। जो मामला दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी के डर से लगातार भूमिगत चल रहा है। विजिलेंस का फेलियर तो देखिए जिन आरोपियों को पकड़ने के लिए दिन-रात छापेमारी करने की बात कही जा रही थी। उन आरोपियों में से कैथल निवासी एक आरोपी प्रवीण सरदाना सरेआम विजिलेंस की नाक के नीचे भाजपा पार्टी के प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में भाग ले रहा है। जिसकी फोटो वह खुद शहर के कई वाट्सएप ग्रुपों में शेयर कर रहा है। विजिलेंस टीम द्वारा आरोपियों की धर-पकड़ के लिए बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं।

लेकिन एक महीने का लंबा समय बीत जाने के बाद भी टीम अभी भी मुख्य आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है, जिसको लेकर अब विजिलेंस की कार्रवाई पर सवाल

उठने लगे हैं। लोगों का कहना है कि विजिलेंस अब राजनीतिक दबाव में काम कर रही। इसलिए जानबूझकर बचे हुए घोटाले बाजों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। दावा यह भी किया जा रहा है कि घोटाले के आरोपियों ने राजनीतिक अप्रोच लगवा इस पूरे मामले को अब ठन्डे बस्ते में डलवा दिया है। इसलिए वह अब धीरे-धीरे अपने बिलों से बाहर निकलना शुरू हो गए हैं।

जिनको शायद अब विजिलेंस की गिरफ्तारी का डर नहीं है। लोगों का यह भी कहना है जब विजिलेंस ने मामला दर्ज होने के तुरंत बाद सात आरोपियों को एक साथ गिरफ्तार कर लिया गया था, तो अब एक महीना बीत जाने के बाद भी बचे हुए शेष आरोपियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा, अगर लोगों की राय सही है तो जाहिर है कि विजिलेंस लाजमी राजनीतिक दबाव में काम कर रही है।

बता दें कि कैथल जिला परिषद में कोरोना काल के दौरान करोड़ों रुपए का सफाई घोटाला सामने आया था। इसमें 10 फर्मों के ठेकेदारों ने अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर ग्रामीण क्षेत्र में बिना विकास कार्य किये ही सरकारी राशि का गबन कर लिया था। यह राशि सीधे अधिकारियों व ठेकेदारों के बैंक खातों में डाली गई थी। 3 साल की लंबी जांच के बाद विजिलेंस द्वारा मई 2024 में इस मामले को लेकर कुल 14 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जिसमें अधिकारियों से लेकर ठेकेदारों के नाम भी शामिल है। विजिलेंस ने इनमें से अभी तक केवल सात आरोपियों को ही गिरफ्तार कर पाई है। घोटाले में संलिप्त एस.डी.ओ, जे.ई व अकाउंटेंट सहित चार ठेकेदार जेल में बंद हैं। उधर विजिलेंस टीम शेष बचे आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर तमाम दावे कर रही है। लेकिन यह दावे असल में धरातल पर कहीं दिखाई नहीं दे रहे।

घोटाले के आरोपी विजिलेंस की तमाम कार्रवाई को धता बता आज भी सरेआम खुले में घूम रहे हैं। कैथल विजिलेंस इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर उनकी दो टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। घोटाले के आरोपी प्रवीण सरदाना की उनके पास कुछ फोटो और वीडियो आई है। जिसको लेकर वह जल्द ही अपनी टीम के साथ पंचकूला जाएंगे। जल्द ही शेष आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

हरियाणा के इस जिले के अस्पताल में शुरू होगा आईसीयू, गंभीर मरीजों को मिलेगा लाभ... नहीं किए जाएंगे रेफर

जींद । नागरिक अस्पताल में अगले सप्ताह से आईसीयू शुरू होने की संभावना है, जिससे जिले के लोगों को बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी। गंभीर मरीजों का इलाज नागरिक अस्पताल में ही संभव हो जाएगा। फिलहाल गंभीर मरीजों को रोहतक पीजीआई या फिर मेडिकल कॉलेज अग्रोहा रेफर करना पड़ता है। पिछले सप्ताह स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक ने आईसीयू शुरू करने के निर्देश दिए थे। आईसीयू के लिए नागरिक अस्पताल को एक चिकित्सक ने ज्वाइन कर लिया है। एक रिटायर्ड फिजिशियन भी जल्द ही अस्पताल में अपनी सेवाएं देने के लिए आ जाएंगे। इससे स्वास्थ्य विभाग को आईसीयू चलाने में आसानी होगी। वहीं डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को तुरंत आईसीयू में छोटी-मोटी कमियों को दूर करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। आईसीयू को पिछले एक सप्ताह से ट्रॉयल के लिए चलाया जा रहा है। इसमें आम मरीजों को दाखिल किया जा रहा है। इससे पता चल जाएगा कि आईसीयू में जो भी कमियां महसूस होंगी, उनको दूर किया जा सके। फिलहाल जो भी स्वास्थ्य विभाग को कमियां मिली हैं, उनको दूर किया जा रहा है। यहां पर सभी बेड पर वेंटिलेटर लगाए गए हैं। फिलहाल आईसीयू में 18 बेड लगाए गए हैं, जिनका लाभ जिले के गंभीर मरीजों को मिलेगा।

नगर पंचायत बैठक में श्रद्धानंद तिवारी किये गए सम्मानित

भटनी देवरिया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नगर पंचायत भटनी की आवश्यक बैठक का आयोजन नगर पंचायत अध्यक्ष विजय कुमार गुप्त की अध्यक्षता में हुआ। इस आवश्यक बैठक में अधिशासी अधिकारी अमित सिंह व सभासद कुन्दन सिंह,सलीम अली,अजीत यादव,सभासद प्रतिनिधि शिव शंकर मौर्य,पारस कुमार,अनिल शर्मा,लालबिहारी प्रजापति व दुर्गेश यादव की मौजूदगी में भटनी नगर के विकास को गति देने पर विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा लोकतंत्र सेनानी श्रद्धानंद तिवारी को फूल मालाओं तथा शाल से सम्मानित किया गया। नगर पंचायत व भटनी के पुल बनाने की लड़ाई में इनका काफी योगदान रहा व किसानों के हित में यह आंदोलन में भी सक्रिय रहे। मंदिर आंदोलन व गौ रक्षा आंदोलन से भी ये जुड़े रहे। लोकतंत्र की रक्षा और संघर्ष करते हुए 18 महीना जेल में भी रहे। इस अवसर पर नगर पंचायत के सभी सम्मानित सभासद गण उपस्थित रहे ।

फ़िज़ा को इंटरमीडिएट में प्रदेश में 8 वीं रैंक लाने पर विधायक ने सौंपा एक लाख का चेक

भटनी देवरिया।

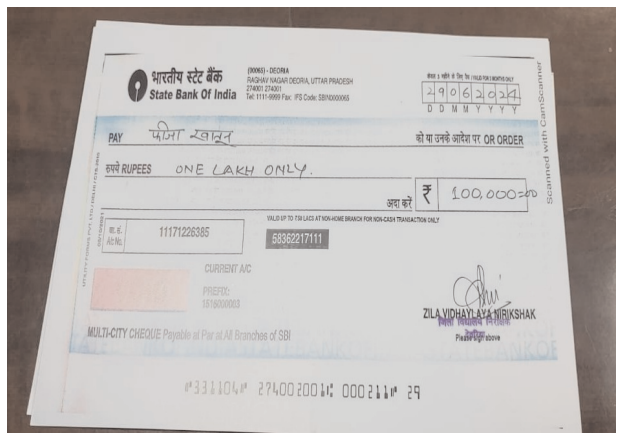

भटनी के सुभाष इंटर कालेज की एक छात्रा फ़िज़ा ख़ातून ने इंटरमीडिएट में 96.40 प्रतिशत अंक प्राप्त कर स्कूल का नाम कर दिया और यह साबित कर दिया है कि अगर कड़ी मेहनत की जाए तो क़ामयाबी मिलनी तय है। बता दें कि भटनी के हरिकीर्तन मोहल्ला की फ़िज़ा ख़ातून पुत्री अशरफ़ अहमद व माता नफ़ीसा ख़ातून ने यूपी में 8 वीं रैंक हासिल कर स्कूल का मान बढ़ाया है। फ़िज़ा शुरू से ही पढ़ने में अव्वल थी और शुरुआती कक्षाओं में भी प्रदर्शन शानदार रहा है। इनकी सफलता पर रामपुर कारखाना विधायक सुरेन्द्र चौरसिया, जिलाधिकारी अखण्ड प्रताप सिंह व मुख्य विकास अधिकारी प्रत्यूष पाण्डेय ने सुभाष इंटरमीडिएट कॉलेज भटनी की छात्रा को एक लाख रुपये, टेबलेट, प्रशस्ति पत्र व मेडल प्रदान किया। इस सम्मान समारोह के बाद सुभाष इंटरमीडिएट विद्यालय परिवार ने फ़िज़ा को बधाई दी है।

सम्मान समारोह में एमएलए, डीएम व सीडीओ ने किया सम्मानित

प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का हुआ प्रसारण

पडरौना,कुशीनगर ।

लगातार तीसरी बार देश की कमान सम्हालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार मन की बात के जरिए रविवार को देश की जनता को संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा मन की बात के 111वें संस्करण को जनपद के 2145 बूथों पर सीधा प्रसारण किया गया जिसमें 32175 लोग सम्मिलित हुए और प्रधानमंत्री के मन की बात को सुनकर उसपर अमल करने का संकल्प लिया। मन की बात के 111वें संस्करण में प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव के बाद राष्ट्र के साथ फिर से जुड़ने पर खुशी जताई, एक पेड़ मां के नाम जैसे अभियान की शुरुआत की। उन्होंने भारतीय संस्कृति के लिए वैश्विक प्रशंसा, आगामी पेरिस ओलंपिक और स्थानीय उद्यमशीलता की सफलताओं पर भी चर्चा की। जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय फाजिलनगर विधानसभा में तुर्कपट्टी मण्डल के बूथ संख्या 244 पर कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात सुनने के बाद कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात देशवासियों को जागृत और प्रेरित करने का महाअभियान है। मन की बात में माननीय मोदी जी ने सभी देशवासियों से ये अपील की है कि अपनी माँ के साथ मिलकर या उनके नाम पर एक पेड़ जरूर लगाएं।

जिलाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से अपील किया कि 6 जुलाई तक चलने वाले वृक्षारोपण कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और कार्यक्रम को सफल बनाए। मन की बात कार्यक्रम के जिला संयोजक व जिला मंत्री विवेकानंद शुक्ल ने बताया कि जनपद में 2145 बूथों पर मन की बात का सीधा प्रसारण के जरिए भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओ सहित 32175 लोगों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात सुनकर उसपर अमल करने का संकल्प लिया।

पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर देवरिया के सुभाष चौक पर कटा केक

देवरिया।

समाजवादी पार्टी के युवा फ्रंटल संगठनो युवजन सभा, लोहिया वाहिनी, यूथ ब्रिगेड एवं छात्र सभा के कार्यकर्ताओ ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर शहर के सुभाष चौक पर केक काटा। इस दौरान केक खिलाकर, मिठाई व फल लोगों के बीच वितरित कर जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान उत्साहित युवा कार्यकर्ताओं ने उनके दीर्घायु होने की कामना की। सपा के जिला उपाध्यक्ष एन.पी.यादव ने कहा कि अखिलेश यादव पिछड़े दलितों एवं अल्पसंख्यकों के सर्वमान्य एवं लोकप्रिय नेता है। वे प्रदेश के गरीबों के सच्चे हमदर्द हैं। सपा नेता विजय रावत ने कहा कि अखिलेश यादव जनता के दिलो में राज करने वाले एकमात्र नेता है। वे देश व प्रदेश के भविष्य है। अखिलेश यादव के नेतृत्व मे सपा लगातार मजबूत हो रही है। सयुस के जिलाध्यक्ष रणवीर यादव ने कहा कि यूपी ही नही अपितु पुरे देश के नौजवान आशा भरी नजरो से अखिलेश यादव के तरफ देख रहे हैं। उनकी विकासवादी सोच उन्हें पूरे देश में लोकप्रिय नेता बनाती है। अखिलेश यादव जी समाज के अंतिम व्यक्ति को खुशहाल बनाने के लिए संघर्षरत है। इस दौरान सयूस जिलाध्यक्ष रणवीर यादव, सलोवा जिलाध्यक्ष दिव्यांश श्रीवास्तव, यूथ ब्रिगेड जिलाध्यक्ष खुर्शीद आलम, छात्र सभा जिलाध्यक्ष मनोज यादव, नसीम लारी, जावेद अंसारी, सूरज यादव, संदीप यादव, काका चौधरी, कमलेश, रूपेश,विवेक रंजन, अहमद मिर्जा, शिवनाथ यादव, बलवंत यादव, राजेश यादव, आनंद यादव, गुड्डू यादव, आकाश,लारेब रहमान, राधेश्याम यादव इत्यादि लोग मौजूद रहे।

रामगढ़ताल में अचानक कैसे मरी मछलियां? पानी के क्लालिटी की होगी जांच- दोषियों पर होगा एक्शन

गोरखपुर ।

गोरखपुर के रामगढ़ताल में मरीं मछलियां निकाल ली गई हैं। शनिवार को ताल की सफाई भी कराई गई। जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन एवं सचिव यूपी सिंह ने भी रामगढ़ताल का निरीक्षण किया। उन्होंने ताल के पानी की गुणवत्ता की जांच के निर्देश दिए हैं। इसके बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारियों ने ताल से नमूने भी एकत्र किए। जीडीए के मुख्य अभियंता किशन सिंह ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी कार्यालय को पत्र भेजकर तीन दिन में रिपोर्ट मांगी है। शुक्रवार को रामगढ़ताल के किनारे बड़ी संख्या में रोहू, भाकुर व अन्य प्रजाति की पाली गईं मछलियां मरी मिलीं। ताल में मछली पालन का व्यवसाय करने वाले मत्स्यजीवी सहकारी समिति के पदाधिकारियों ने ताल का पानी कम होने और तल गरम होने से मछलियां मरने की बात कही। वहीं, पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि ताल के पानी में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम होने पर जलीव जीव मरने लगते हैं। रामगढ़ताल में भी ऐसा ही हुआ होगा। मछली पालकों ने 40 से 50 लाख रुपये के नुकसान की आशंका जताई है। वहीं ताल के पानी से उठ रही बदबू के चलते किनारे टहलने वाले भी परेशान दिखे। मामला सामने आने के बाद जल निगम ने कुछ ही देर बाद ताल के पानी को शुद्ध होने का दावा भी कर दिया। मछलियों के मरने से बिगड़ रही स्थिति को देखते हुए मछली पालकों ने पांच नाव लगाकर मछलियों को हटवाना शुरू किया। शुक्रवार व शनिवार को ताल की सफाई भी कराई गई। शनिवार की सुबह तक मरीं मछलियों को निकाल लिया गया था, जिससे ताल से बदबू आनी बंद हो गई। दोपहर में जीडीए उपाध्यक्ष व सचिव ने ताल का निरीक्षण कर पानी की गुणवत्ता जांचने के निर्देश दिए।

नया सवेरा से चिड़ियाघर तक लिया गया सैंपल

जीडीए की तरफ से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पत्र भेजकर नया सवेरा से लेकर चिड़ियाघर की ओर जाने वाली सड़क से लगे ताल के पानी का सैंपल लेने के लिए कहा गया है। तीन दिन में जांच रिपोर्ट और विभागीय राय भी मांगी गई है। उधर, शनिवार दोपहर में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारियों ने ताल से नमूने भी एकत्र किए। प्राधिकरण के मुख्य अभियंता किशन सिंह का दावा है कि तीन दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। हालांकि मछलियों के पोस्टमार्टम कराने की पहल न तो मछली पालन का ठेका लेने वाली मत्स्यजीवी सहकारी समिति ने की और न जीडीए ने ही इस पर ध्यान दिया। मत्स्यजीवी सहकारी समिति के अध्यक्ष मदन लाल व सचिव बलदेव सिंह ने कहा कि अधिकांश मृत मछलियों को ताल से निकाला जा चुका है।

गोरखपुर विश्वविद्यालय से भी ली जा सकती है मदद

जीडीए रामगढ़ताल में मछलियों के मरने के कारणों की जांच के लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से भी मदद ले सकता है।

विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान विभाग की ओर से ताल के पानी की गुणवत्ता को लेकर कई बार अध्ययन किया जा चुका है। एक बार भारी मात्रा में मछलियां मृत पाई गई थीं, जिसके बाद विभाग ने अध्ययन कराया था। इसमें ताल के पानी में ऑक्सीजन की कमी मिली थी। चर्चा है कि इस बार भी प्राधिकरण की ओर से विश्वविद्यालय को पत्र लिखा जा सकता है।

करूज, बोट संचालकों को दी गई चेतावनी

निरीक्षण के लिए पहुंचे जीडीए उपाध्यक्ष ने करूज और बोट संचालकों को निर्देश दिया है कि वे यह सुनिश्चित कराएं कि यात्रा करने वाले लोगों के हाथ में पानी की बोतल, रैपर आदि न हो। यदि ताल के पानी में बोतल या रैपर फेंककर गंदगी की गई तो संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। एक्सपर्ट कमेंट के तौर पर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, गोंडा के कार्यकारी निदेशक प्रो गोविंद पांडेय ने बताया कि रामगढ़ताल में जिस तरह से सिर्फ बड़ी मछलियां मरी हैं, यह ऑक्सीजन की कमी की ओर इशारा कर रही है। इस तापमान में रामगढ़ताल में एल्गल ब्लूम हो जाता है। इससे शैवालों की संख्या बढ़ जाती है और पानी हरा नजर आने लगता है। इस स्थिति में घुलित ऑक्सीजन की खपत भी बढ़ जाती है। इससे पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिसका असर उसमें रहने वाले जीव-जंतुओं पर होता है।

आयुक्त, दि.न.नि की लापहरवाही के कारण

रोहिणी जोन, एम-1 के वार्डो में गली, नाली/नाला, सड़क,पुलिया, पार्क, फुटपाथ के विकास एवं निर्माण कार्यो में करोड़ो का घोटाला व भ्रष्टाचार की श्रीमान निदेशक, सी.बी.आई, भारत सरकार से जांच की मांग।

अधिशासी, सहायक व कनिष्ठ अभियंता बने "अडानी"

एम-1, वर्क्स विभाग, रोहिणी जोन के ई.ई श्री राकेश अहुजा, ए.ई श्री योगेन्द्र कुमार, अनूज कुमार, जे.ई श्री दीपक लाल, दीपांशू, रोहित शर्मा की मिलीभगत से किए करोड़ो के घोटाले ही घोटाले.....

वार्ड-21, 22, 23, 24, 25, 52, 53, 54 में किये जा रहे व किये गए विकास एवं निर्माण में लगाई बेहद घटिया निर्माण सामग्री, एमसीडी को लगाया अभियंताओं ने करोड़ो का चूना।

आलोक कुंज अपार्टमेंट, गेट नं.-5, गेट नं.-6, गेट नं.-7, सेक्टर-15, रोहिणी, ए-5/26, सेक्टर-15, रोहिणी, एसटी. एंजल स्कूल, ए-ब्लॉक, सेक्टर-15, रोहिणी के सड़को पर

"आचार्य श्री तुलसी मार्ग", सेक्टर-5 वार्ड-25 (एन) में रोड़ जे.आई.एम.एस.कॉलेज से सीबीसी-4 मार्किट तक की सड़क

अभियंताओं ने बनाई करोड़ो रूपये की बेनामी सम्पत्ति खरीदी अपने व अपने रिश्तेदारों के नाम महंगी-महंगी लग्जरी कारें उसपर 40-40 हजार के ड्राईवर से चलते है, स्वयं व इनके परिवार

एप्पल का मोबाईल व लेपटॉप और पी.पी.डिजाईनर के कपड़े, रोलेक्स की घड़ी, बूची के जूते, लग्जरी कारो स्वंय व परिवार के लिए प्राईवेट ड्राइवर 40-40 हजार प्रतिमाह, शाम का डिनर बड़े रेस्टुरेंट, होटल और क्लबों और लाखों की ज्वैलरी और अडानी की तरह आलीशान जिन्दगी जी रहे है।

अध्यक्षः अपराध एवं भ्रष्टाचार निरोधक मोर्चा

विज्ञापन-जनहित में जारी.....

कोमलकांत प्रधान, अधीक्षण अभियंता, शाहदरा अनुरक्षण जोन के संरक्षण में

कार्यपालक अभियंता, लो.नि.वि, शाहदरा रोड़ डिवीजन

द्वितीय निजामुद्दीन ब्रिज, एनएच-24, बाईपास, पूर्वी एप्रोच, कार्यालय बना भ्रष्टाचार का अड्डा!

कार्यपालक, सहायक, कनिष्ठ अभियंता बने ''अडानी''

ई.ई चंदन कुमार, उपखण्ड-1,2,3,4 ए.ई अमरेन्द्र कुमार, शुभ नारायण सिंह, विनोद कुमार सिंह, अमरेश कुमार मीणा, जे.ई व ठेकेदार की मिलीभगत से किए सड़को, फुटपाथ व नालो के निर्माण कार्य में करोड़ो के घोटाले...

''जी.टी.रोड़'', शाहदरा की सड़क

''जी.टी.बी.हॉस्पिटल रोड़'', रोड़-64 से 68 की सड़क

शाहदरा बॉर्डर, बस स्टेण्ड अण्डरपास आनन्द विहार की ओर जाने वाली सड़क

- जी.टी.रोड़, धरमपुरा टी-पांईट से अपसरा बॉर्डर ओवर की सड़क
- गीता कॉलोनी यमुना ब्रिज रोड़, रिंग रोड़ क्रॉसिंग से पुस्ता रोड़ की सड़क
- ऋषभ विहार रोड़ की सड़क
- लेबर चौक सीमापुरी लिंक रोड़ की सड़क

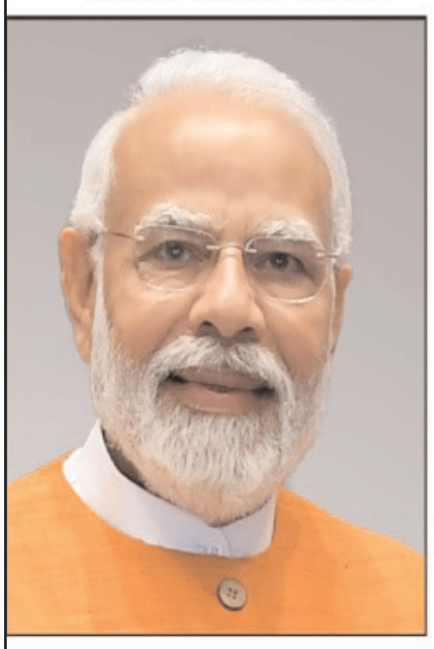

माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी, शाहदरा रोड़ डिवीजन, लो.नि.वि, कार्यालय में तीन वर्षो से चल रहे भ्रष्टाचार की जांच निदेशक, सी.बी.आई से कराने की मांग।

सड़को, फुटपाथ, डिवाईडर व नालो के निर्माण कार्य की काली कमाई से अधी० अभियंता

ई.ई चंदन कुमार, ए.ई अमरेन्द्र कुमार, शुभ नारायण सिंह, विनोद कुमार सिंह, अमरेश कुमार मीणा, जे.ई बने 'अडानी'

करोड़ो रूपये की बेनामी सम्पत्ति खरीदी अपने व अपने रिश्तेदारों के नाम

महंगी-महंगी लग्जरी कारों से चलते है, स्वयं व इनके परिवार

एप्पल का मोबाईल व लेपटॉप और पी.पी.डिजाईनर के कपड़े, रोलेक्स की घड़ी, बूची के जूते, लग्जरी कारो स्वंय व परिवार के लिए प्राईवेट ड्राइवर 20-20 हजार प्रतिमाह, शाम का डिनर बड़े रेस्टुरेंट, होटल और क्लबों और लाखों की ज्वैलरी और अडानी की तरह आलीशान जिन्दगी जी रहे है।

निवेदकः अपराध एवं भ्रष्टाचार निरोधक मोर्चा

विज्ञापन-जनहित में जारी.....

Email: abnmdp@gmail.com